प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
11.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत असर पड़ा और भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्ष के कार्यकाल में 54 हजार 2 सौ 96 करोड़ रुपये की आरडीजी मिली थी। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों व संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17 हजार 5 सौ 63 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य की मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में आज पत्रकारा वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए और लगातार फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से सीपीएस लगाए और सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की पैरवी करने के लिए वकीलों को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डों में बड़ी संख्या में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तैनात किए गए हैं और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बिंदल ने कहा कि आरडीजी बंद होने से नहीं राज्य सरकार के कुप्रबंधन से ही प्रदेश आज आर्थिक बदहाली की दहलीज पर पहुंच गया है।

जयराम ठाकुर

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 16वें वित्तायोग मे राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने का ऐलान अभी किया है लेकिन इस बारे में 12वें वित्तायोग के समय से ही चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए और राज्य को आर्थिक कंगाली की कगार पर धकेला। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये केंद्र की ओर से विशेष मदद है।

इंदू गोस्वामी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए हिमाचल सरकार को लगभग 3 सौ 70 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक ये भूमि नहीं दी गई है। राज्यसभा में सांसद इंदू गोस्वामी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन देना

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा भी प्रदेश सरकार की प्रदान करेगी।

इंदू गोस्वामी के एक अन्य सवाल पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि युद्ध विधवाओं को ई.सी.एच.एस. योजना के तहत सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक मुश्त योगदान से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड हवलदार या बराबर रैंक के पूर्व फौजियों या युद्ध विधवाओं की दो बेटियों की शादी के लिए एक–एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करता है।